(ग) क्या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में भी गैस की नई एजेंसियां आवंटित करने का निर्णय किया गया है और;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और ये कहां-कहां आवंटित की जाएंगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों ने अपने वार्षिक कार्यक्रम के भाग के रूप में वर्ष 1980-81 के दौरान देश के विभिन्न भागों में कुल 235 नई खाना पकाने की गैस की एजेंसियों की स्थापना के सम्बंध में योजनाएं आरम्भ की है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) क्योंकि मिर्जापुर में स्थित वर्तमान वितरक 2500 रिफिल्स प्रति माह की निर्धारित सीमा से बहुत नीचे कार्य कर रहा है, किसी अतिरिक्त वितरक की उस स्थान के लिए योजना बनाई गई है ।

विवरण

राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नाम	कुल
1	2
आन्ध्र प्रदेश	26
असम	02
बिहार	08
गुजरात	22
हरियाणा	12
कर्नाटक	29
मध्यप्रदेश	17
महाराष्ट्र	25
उड़ीसा	02
पंजाब	15
राजस्थान	15
तमिल नाडु	12
उत्तर प्रदेश	20
पश्चिम बंगाल	07
चण्डीगढ़	02
दिल्ली	20
गोआ	01
कुल	235

नये पेट्रोल पम्पों की स्थापना

177. **श्री राम प्यारे पनिका : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या इस वर्ष कुछ नये पेट्रोल पम्पों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा प्रस्तावित स्थान कौन से हैं ;

(ग) क्या जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में भी कुछ पेट्रोल पम्पों की स्थापना का निर्णय लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या तथा स्थान क्या हैं और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) तेल उद्योग ने खुदरा बिक्री केन्द्र (रिटेल ग्राउटलेट डीलरशिप) खोलने के उद्देश्य से एक रोलिंग रजिस्टर बनाया हुग्रा है । 1980-81 में लगभग 551 नये खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल पम्प) खोलने के लिए ग्रन्तिम निर्णय/विज्ञापित किया गया है जहां देश भर में विभिन्न स्थलों पर वितरकों का या तो चयन कर लिया गया है या उनका चयन किया जा रहा है । स्थलों का ब्यौरा तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी हां ।

(घ) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कुल मिलाकर सात स्थल विज्ञापित किये गये हैं । उन स्थलों के नाम हैं : ग्रन्नापारा, शक्ति नगर वन्दामगंज, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर मिर्जापुर शहर, सुकरात, राजगढ़ तथा ग्रण्डीमोर ।

Illegal Screening of Films

178. SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to illegal and unauthorised screening of Bombay hit films almost all over the country resulting in huge losses of taxes;

(b) whether it is a fact that large stocks of raw films have been seized in raids on Bombay film laboratories; and

(c) if so, the extent of loss to the exchequer and nature of preventive steps taken in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) to (c) The in formation is being collected from the various States/Departments concerned and will be laid on the Table of the House.

Working Group to consider price of Coking and Non-coking Coal

179. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have set up a working group to consider the Price issue of all grades of coking and non-coking coal to meet the rising production costs;

(b) whether the working group has made the recommendations in this regard; and

(c) if so, the details thereof and Government's decision on it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (c). A group was constituted to undertake a study of the cost of production of coal and suggest an appropriate price for coal. On the basis of such a study the average pit-head prices of coal produced by Coal India Ltd. and Singareni Colleries Company Ltd., have been fixed by Government at Rs. 128.02 and Rs. 136.85 per tonne respectively with effect from 14th February, 1981.

Assistance by Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry in Off-Shore Oil Exploration

180. SHRI R. L. BHATIA:
SHRI CHANDRADEO PRASAD VERMA:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) has offered the assistance of the private sector in off-shore oil exploration as well as supply of equipment being produced within the country;